315.00 in July 1996 to Rs. 515.50 as on 23.7.1997.

(b) Does not arise

(c) and (d) ITC Ltd as such is a profit making company. As regards large arrears of excise, IDBI has reported that there was a differential excise duty demand of Rs. 681.54 crore and the company has deposited Rs. 350 crore and also has furnished a bond to the Excise Directorates. The company has gone on appeal against order of the Commissioner.

(e) and (f) The investigations under the Foreign Exchange Reglation Act, 1973 undertaken by the Enforcement Directorate against the company are continuing.

Army's Protest against Broadcasting of Serials Defaming Police and Military

744. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Army has protested against the Zee serial "Brigadier Balwant Bhawan" as the same is derogatory to war widows;

(b) whether there have been other cases also of defamation of police and military i.e. "Maachis" and "Adavilo Anna" - Brother in Forest as reported in 'The Pioneer', dated 25th January 1997;

(c) whether authorities in Hyderabad have objected to Pakistani T.V. programmes on cable as anti-police and anti-military; and

(d) whether Government would consider having an army and/or police representative on Censor Board and various monitoring committees?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) The Chief of Army Staff has filed a petition in the High Court of Delhi against ZEE TV for the serial "Brigadier Balwant Bhawan". The matter is sub-judice.

(b) The film ' Maachis' and 'Adavilo Anna' were examined and passed by the Central Board of Film Certification. It has come to the notice of this Ministry that a writ petition was filed by the Andhra Pradesh Police Officers' Association against the producers of the film 'Adavilo Anna' in the Andhra Pradesh High Court. However, the petition was dismissed by the Hon'ble Court.

(c) Government is not aware of any such objections.

(d) There is no such proposal under consideration of the Government.

नौवीं योजना के अन्तर्गत नई मूल्य एवं सूचनात्मक सेवाओं की जरूरत पर विशेषज्ञों के पैनल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

745. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रसारण क्षेत्र में नई मूल्य एवं सूचनात्मक सेवाओं तथा इंटरनेट सेवाओं की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए गठित किए गए विशेषज्ञों के पैनल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या उक्त योजनावधि में राज्यों में कार्यक्रम निर्माण संबंधी नए स्टूडियो और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात के जामनगर शहर में एक पूर्णकालिक कार्यक्रम निर्माण स्टूडियो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां , तो अनुमानित लागत के अनुसार उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी): (क) इस मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों का ऐसा कोई पैनल गठित नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) हालांकि वर्तमान में 25 स्टूडियो और भिन्न-भिन्न शक्तियों के 247 टी.वी. ट्रांसमीटर विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयनाधीन हैं तथापि अतिरिक्त 7 स्टूडियो और 107 ट्रांसमीटरों के कार्यान्वयन को दूरदर्शन की नौवीं योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते योजना आयोग द्वारा मंजूरी दे दी जाए और संसाधन एवं अपेक्षित आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।